बांग्लादेशः एक राष्ट्र के रुप में धार्मिक बनाम सांस्कृतिक अर्न्तद्वन्द का परिणाम

डा. विनय बहादुर पाण्डेय
पा"चात्य इतिहास विभाग
लखनऊ वि"वविद्यालय, लखनऊ

सन 1971 में जन्मे बाँग्लादेश के अभ्युदय से पाकिस्तान का इतिहास तो परिवर्तित हुआ ही, भूगोल भी अप्रभावित न रह सका। बदलते हुए भूगोल में एक नए राष्ट्र का उदय हुआ जिसे बाँग्लादेश की संज्ञा दी गयी। बाँग्लादेश पाकिस्तान बनने से पूर्व अविभाजित भारत के 'वृहत्तर बंगाल' का ही एक भाग था जो मुस्लिम सल्तनत का एक सुदूरवर्ती राज्य था। ब्रिटिश भारत में यही एकमात्र ऐसा राज्य था, जहाँ मुस्लिम लीग की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी थी। 20 जून 1946 को बंगाल विधानसभा के सदस्यों ने मतदान द्वारा पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला लिया, हिन्दू सदस्यों ने इस फैसले का विरोध करते हुए बंगाल–विभाजन की माँग की, जिसके आधार पर बंगाल का विभाजन कर पश्चिमी बंगाल को भारत का और पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया।इस प्रकार भारत और पाकिस्तान के विभाजन के फलस्वरूप पूर्वी बंगाल राज्य पाकिस्तान के अधीन पहले पूर्वी पाकिस्तान और बंगालियों के संघर्ष के फलस्वरूप दिसम्बर 1971 में बाँग्लादेश बना।

पूर्वी पाकिस्तान में विभाजन के बीच भारत–पाक बँटवारे के तुरन्त बाद ही बोये जा चुके थे। पाकिस्तानी पूँजीपतियों और नौकरशाहों ने गरीबी से जूझ रही बंगाली जनता को आर्थिक विकास से वंचित कर रखा था।सीटों के अन्याय वितरण के साथ ही पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों की या तो सरकार बनने ही नहीं दी गयी और यदि बनी भी, तो उसे पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाबियों और पठानों द्वारा अपदस्थ करने में देरी नहीं की गई। मार्च 1954 के प्रान्तीय चुनाव में मुस्लिम लीग के प्रत्याशियों को हराकर संयुक्त मोर्चे के नेता ए0के0 फजलुलहक ने पूर्वी पाकिस्तान की प्रादेशिक सरकार गठित करने का हकतो प्राप्त कर लिया, किन्तु दो महीने के अन्दर ही 30 मई 1954 गर्वनर जनरल गुलाम मोहम्मद ने एक आदेश द्वारा नया मंत्रिमण्डल भंग कर गर्वनर शासन लागू कर बंगालियों की प्रिय सरकार का सफाया कर दिया। इसी प्रकार पाकिस्तान की सरकार पूर्वी पाकिस्तान के मताधिकार की उपेक्षा कर रही थी। पाकिस्तान के पूर्वी तथा पश्चिमी भागों के मध्य जनता के संघर्ष में आर्थिक कारण की अपेक्षा कहीं अधिक जातीय, सांस्कृतिक, भाषाई और राजनीतिक कारण था। जहाँ पूर्वी पाकिस्तान के लोग मूलतः बंगाली थे जो साहित्य संगीत और सांस्कृतिक कार्यकलापों में निपुण थे जिसका पश्चिमी पाकिस्तान के लोग मजाक उड़ाते थे और उनके सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की प्रशंसा नहीं करते थे। पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों में सांस्कृतिक परम्पराओं का सर्वथा अभाव था अतः उन्होंने बंगला भाषा की उपेक्षा कर अपनी पंजाबी, सिन्धी और बलूची आदि भाषाओं को ज्यादा अच्छा माना तथा राष्ट्रीय भाषा के रूप में उर्दू की मान्यता दी।

फरवरी 1948 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पूर्वी पाकिस्तान की अपनी पहली तथा अन्तिम यात्रा के दौरान बहुमत का तिरस्कार करते हुए इस बात पर बल दिया था कि पाकिस्तान की एक

भाषा उर्दू ही रहेगी। जबकि वास्तविकता यह थी कि पूर्वी पाकिस्तान की 7.2% से भी कम जनता द्वारा ही उर्दू भाषा बोली जाती थी। जिन्ना स्वयं भी उर्दू नहीं जानते थे। उनके सार्वजनिक भाषण हमेशा अंग्रेजी में होते थे अतः वे कैसे राष्ट्रीय भाषा उर्दू पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर थोप सकते थे। इस प्रकार भारत–पाक विभाजन के तुरन्त बाद पाकिस्तान में उत्पन्न भाषायी विवाद ने पाकिस्तान के दोनों भागों के मध्य कड़वाहट बढ़ा दी। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने विद्रोह कर दिया, जिसके फलस्वरूप उर्दू थोपने के विरूद्व आन्दोलन करते हुए ढाका में 03 छात्र 21 फरवरी 1952 को गोलाबारी में मारे गये और कुछ घायल भी हुए। ढाका में वहाँ पर एक शहीद मीनार बनवाई गई। उस दिन को वहाँ शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।इस घटना के बाद पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को एहसास हो गया कि उन्हें अपने अधिकारों के लिएलड़ना पड़ेगा।लेकिन इस विद्रोह के बाद अन्ततोगत्वा पाकिस्तानी सरकार में बंगाली को उर्दू के समान राज्य भाषा स्वीकर करने के लिए विवश हुई। 1956 तथा 1962 के अयूब के संविधान में उर्दू और बंगाली को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया, किन्तु फिर भी बंगालियों को एक लम्बे समय तक राजनैतिक अवमानना सहन करने के साथ ही साथ सांस्कृतिक उत्थान के प्रथम सोपान (अपनी मातृभाषा) की प्राप्ति में सौतेला व्यवहार का विषैला घूट पीना पड़ा। जिसने पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया। बंगाली को राष्ट्रीय भाषा की मान्यता के प्रयत्न ने बंगालियों को यह सोचने पर विवश कर दिया कि उनके साथ पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा जबरन नियन्त्रण में रखने का षड़यन्त्र किया जा रहा है और वास्तविक उद्देश्य को छिपाने के लिए इस्लाम का आश्रय लिया जा रहा है। राजनीतिक एवं भाषाई दृष्टि से बंगालियों को प्रताड़ित करने के साथ ही पाकिस्तानी शासकों ने बंगालियों की इस्लाम भक्ति को भी आशंका की दृष्टि से देखा। बंगालियों को काफिर कहकर तिरस्कृत कियज्ञं

पूर्वी पाकिस्तान संस्कृति एवं भाषाई समानता तथा जनंसख्या की दृष्टि से पश्चिमी पाकिस्तान की तुलना में श्रेष्ठ होने के बावजूद पाकिस्तानी शासकों ने दोनों भागों में समुचित संतुलन बनाये रखने की दृष्टि से बंगालियों को उनके लाभों से वंचित रखने का प्रयत्न किया। बंगालियों को शिक्षा, सामाजिक कल्याण, नौकरियों आदि की दृष्टि से भी पश्चिमी पाकिस्तान की तुलना में उपेक्षित समझा गया। यही कारण था कि पूर्वी पाकिस्तान में प्राइमरी स्कूलों में जाने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि के बावजूद स्कूलों की संख्या क्रमशः कम होती गयी और पश्चिमी पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान की अपेक्षा प्राइमरी स्कूलों की संख्या चार गुना बढ़ा दी गई। 1947–48 में पश्चिमी पाकिस्तान में प्राइमरी स्कूलों की संख्या 8413 थी जो 1968–69 में बढ़ाकर 39418 कर दी गई जबकि पूर्वी पाकिस्तान में इन्हीं विद्यालयों की संख्या 1947–48 में 29663 थी और 1968–69 में बढ़ाकर 28308 कर दी गई। इस प्रकार पूर्वी पाकिस्तान ने यह महसूस किया कि पश्चिमी पाकिस्तान उनके साथ उपनिवेशों जैसा व्यवहार कर रहा है। जूट उद्योग से अच्छी खासी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती थी, जिसका उपयोग पश्चिमी पाकिस्तान के विकास के लिए किया जाता था।

इस प्रकार पूर्वी पाकिस्तान ने यह महसूस किया कि पश्चिमी पाकिस्तान उनके साथ उपनिवेशों जैसा व्यवहार कर रहा है। जूट उद्योग से अच्छी खासी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती थी, जिसका उपयोग पश्चिमी पाकिस्तान के विकास के लिए किया जाता था। इसी प्रकार 1965 में ही रूस ने पश्चिमी पाकिस्तान के तेल उद्योग के लिए 11 मिलियन से 18 मिलियन पौंड धनराशि दी तथा 1947–1965 के मध्य ब्रिटेन द्वारा दिये गये 64 मिलियन पौण्ड के कर्जो की धनराशि का अधिकांश भाग पश्चिमी पाकिस्तान पर ही व्यय किया गया। इसी प्रकार विश्व की अधिकांश सहायता पश्चिमी पाकिस्तान तक ही सीमित रही। अमेरिका के द्वारा सहायता के रूप में दी गई 3.6 मिलियन डालर की धनराशि में 2.7 मिलियन डालर पश्चिमी पाकिस्तान के मंगला और तरबेला बाँधों के लिए और केवल 0.9 मिलियन डालर पूर्वी पाकिस्तान बाढ़ को नियन्त्रित करने के लिए रखी गई।

पाकिस्तान कृषि बैंक द्वारा 600 मिलियन रू0 की धनराशि दी गई किन्तु उसका अधिकांश भाग पश्चिमी पाकिस्तान की भूमि के विकास पर ही व्यय किया गया। केन्द्रीय सरकार के सहयोग से बड़ी–बड़ी सिंचाई योजनायें भी पश्चिमी पाकिस्तान में पूरी की गईं। अतः घनी आबादी वाले पूर्वी भागमें कृषि विकास के अपेक्षित होने से उन्हें भरपेट भेजन तक के लिए मोहताज होना पड़ा। औद्योगिक प्रगति की दृष्टि में भी पश्चिमी पाकिस्तान की तुलना में पूर्वी पाकिस्तान काफी पीछे रह गया। पाकिस्तान में कुल 29 औद्योगिक केन्द्रों में सिर्फ दो केन्द्र बंगाली थे।सामान्यतया औद्योगिक प्रगति का यह प्रतिशत पश्चिमी पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान की अपेक्षा 3 गुना था।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूर्वी पाकिस्तान के सभी उद्योग पश्चिमी पाकिस्तान के उद्योगपतियों द्वारा ही स्थापित और नियंत्रित किये जाते थे। ये उद्योगपति इन्हें पूर्वी पाकिस्तान के समृद्धि में हाथ बटाने के बजाय पश्चिमी पाकिस्तान की ओर ही हस्तान्तरित करने का प्रयास करते थे। चूँकि प्राइवेट पूँजी लगाने पर पूर्वी पाकिस्तान का कोई नियंत्रण नहीं था। बिजली के उपभोग का अनुपात, जिसे प्रगति का मापक माना जाता है, पूर्वी पाकिस्तान में कम रहा। साथ ही साथ शक्ति का उत्पादन भी कम रहा। पश्चिमी पाकिस्तान में शक्ति का उत्पादन 838000 किलोवाट रहा, वहीं पूर्वी पाकिस्तान का 179500 किलोवाट था। पाकिस्तान की कुल शक्ति उत्पादन का 85% पश्चिमी पाकिस्तानमें तथा 15% पूर्वी पाकिस्तान में था।

इस प्रकार की आर्थिक असमानता ने राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों में असन्तुलन उत्पन्न कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान की जनता की कुंठा और आक्रोश की भावना से पश्चिमी पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार के गठबंधन में विश्वास नहीं रहा। अयूब खाँ को पूर्वी बंगालियों की राजनैतिक प्रतिक्रिया का आभास था और उनको मानसिक भय प्रदत्त करने हेतु प्रशासन ने 30 जनवरी 1962 को शहीद सुहरावर्दी को बन्दी बना लिया। फरवरी 1962 में छात्रों ने हड़ताल कर दी और ढाका विश्वविद्यालय बन्द कर दिया गया। ऐसी विषम परिस्थिति को देखते हुए अयूब खाँ ने पूर्वी बंगाल के लोगों को सुविधायें प्रदान करने की घोषणा की, जिसमें पाकिस्तान के औद्योगिक विकास निगम, रेलवे बोर्ड तथा जल विद्युत विकास निगम को दो भागों में विभक्त कर दिया गया। अयूब खाँ की इस घोषणा का छात्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 15 मार्च 1962 को ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने पुनः हड़ताल कर दी। अयूब ने इस हड़ताल में विदेशियों का हाथ बताया। 1962 से 1964 के अन्त तक पाकिस्तान के प्रशासन और पूर्वी पाकिस्तान में संघर्ष चलता रहा। 1964 में ढाका विश्वविद्यालय में प्रदर्शन प्रारम्भ हो गये, इस प्रदर्शनों में छात्राओं ने भी भाग लिया। इन प्रदर्शनों का व्यापक प्रभाव पूर्वी बंगाल पर पड़ा।

इसी मध्य अयूब खाँ ने राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा का कार्य प्रारम्भ कर दिया और 1962 में अयूब खाँ फातिमा जिन्ना को हराकर विजयी हुए। राष्ट्रपति अयूब की पूर्वी बंगाल श्रमिक और रेलवे की हड़तालों में दमनकारी नीति ने वातावरण को विषम कर दिया। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले ताशकंद समझौते का पाकिस्तान में विरोध किया गया, परन्तु पूर्वी बंगाल के राजनीतिज्ञों ने स्वरक्षा एवं व्यापार के नाते भारत से मेलजोल बनाये रखा, जिससे अयूब खाँ बंगालियों से घृणा का भाव रखने लगे। 1966 के प्रारम्भ में राजनैतिक दलों एवं छात्र संगठनों ने युद्ध के दौरान आरोपित आपातकालीन स्थिति को समाप्त करने की माँग की। 26 फरवरी 1966 को मौलाना भसानी के सहयोग से पूर्वी पाकिस्तान में आपातकालीन मुक्ति दिवस मनाया गया। फरवरी 1966 में शेख मुजीब ने लाहौर के एक प्रस्ताव में छः सूत्रीय माँग रखी। मार्च 1966 में शेख मुजीब की 6 सूत्रीय योजना का प्रकाशन हुआ। इस 6 सूत्रों ने पश्चिमी पाकिस्तान के प्रशासन में सनसनी मचा दी।

फरवरी 1966 में शेख मुजीब की अवामी लीग द्वारा 6–सूत्रीय योजना को लागू करने के तुरन्त बाद अयूब ने मुजीब को अलगाववादी की संज्ञा दे दी। अयूब खाँ और उसकी सरकार ने लोकप्रिय आन्दोलन को दमन करने के लिए कठोर कार्यवाही आरम्भ कर दी। शेख मुजीब को बन्दी बना लिया गया।इसी बीच 7 नवम्बर 1968 को पूर्वी पाकिस्तान में भी छात्रों का आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। धीरे–धीरे श्रमिक तथा निम्नवर्ग ने भी आन्दोलन में भाग लेना प्रारम्भ कर दिया। हिंसा और हत्याओं में वृद्धि के साथ ही आन्दोलन त्वरित होने लगा। दिसम्बर 1968 से फरवरी 1969 के मध्य 117 लोगों को मार दिया गया, 464 लोग घायल हुई, 1500 लोगों को बन्दी बनाया गया।जनवरी 1969 के आरम्भ में पूर्वी पाकिस्तान के छात्रों ने एक शक्रियाशील पूर्वी पाकिस्तान समितिश का संगठन किया और 11 सूत्रीय कार्यक्रम का माँग पत्र प्रेषित किया। इस माँग पत्र में शिक्षा में सुधार के अतिरिक्त पाकिस्तान की संसदीय प्रणाली, संघीय सरकार के अधिकार, राष्ट्रीयकरण, विदेशनीति तथा राजनैतिक बन्दियों के प्रति उदारता की माँगें थीं। यह छात्र क्रियाशील समिति पूर्वी पाकिस्तान का शक्तिशाली संगठन बन गया। 17 जनवरी 1969 को माँग दिवस मनाया गया। ढाका में 23–24 जनवरी की रात्रि को 25 हजार छात्रों ने ष्टार्च जुलूसष निकाला और यह शपथ ली कि जब तक 11 सूत्रीय माँग पत्र स्वीकृत नहीं हो जाएगा, तब तक संघर्ष करते रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप पुलिस के गोली काण्ड के कारण कई हत्यायें हुईं। मुजीब ने इस मध्य पैरोल पर छूटने से इन्कार कर दिया और ढाका की आम सभा में जिसके मुख्य वक्ता मौलाना भसानी थे, जिन्होंने मुजीबुर्रहमान को बिना शर्त रिहा करने की माँग रखी।

25 मार्च 1969 को मोहम्मद अयूब द्वारा जनरल याहिया खाँ को सत्ता सौप दी।7 दिसम्बर 1970 को पाकिस्तान में राष्ट्रपति याहिया खाँ ने चुनाव करा ही दिये थे, जो कि पिछले तेरह साल से सिर्फ एक सपना था।पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित इस चुनाव में कुल 300 स्थान थे, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान के लिए 138 स्थान थे और पूर्वी पाकिस्तान के लिए 162 स्थान थे। इस आम चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान में अवामी लीग जो कि मुजीबुर्रहमान की पार्टी थी तथा पश्चिमी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी थी, को सफलता प्राप्त हुई।शेख मुजीबुर्रहमान की अवामी को पूर्वी पाकिस्तान की कुल 162 सीटो में से 160 सीटें प्राप्त हुईं तथा जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को पश्चिमी पाकिस्तान की 138 सीटो में से 81 सीटें प्राप्त हुईं।इस प्रकार शेख मुजीबुर्रहमान की पार्टी को पाकिस्तान की नवनिर्वाचित राष्ट्रीय सभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया। इसका अर्थ था कि पाकिस्तान में सत्ता का ताज शेख मुजीबुर्रहमान को पहनाया जायेगा, परन्तु याहिया खाँ मुजीब को सत्ता सौपना नहीं चाहते थे। याहिया खाँ की सत्ता के विरोध में अवामी लीग द्वारा 7 मार्च 1971 को ढाका के रमन रेसकोर्स मैदान एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें लाखों लोगों की भीड़ जमा हो गयी। इस सभा को शेख मुजीबुर्रहमान ने सम्बोधित किया। मुजीब ने भुट्टो को अल्पमत वाली पार्टी का नेता बताया और उन पर हमेशा गैरजिम्मेदाराना कार्य करने का आरोप लगाते हुए घोषणा की कि श8 मार्च से सरकार को न तो करों की अदायगी होगी और न राजस्व मिलेगा। सरकारी दफ्तर, न्यायालय और स्कूल बन्द रहेंगे।सिर्फ दो घण्टे के लिए बैंक खुलेंगे। यदि हम पर एक भी गोली बरसाई जायेगी तो हम घर–घर को किला बना देंगे। इसके साथ ही मुजीब ने लाखों की भीड़ के समक्ष पूर्वी बंगाल के मुक्ति हेतु हर सम्भव कुर्बानी का संकल्प लिया और बाँग्ला देश के नागरिकों से तानाशाही के विरुद्ध लोहा लेने का आवाहन किया। 15 मार्च को शेख मुजीबुर्रहमान ने बाँग्लादेश के निर्माण की घोषणा कर दी। इस अवसर पर उन्होंने पैंतीस आदेश जारी किए। शेख मुजीब के इस प्रकार के कदम उठाने की बात को सुनते ही याहिया खाँ 15 मार्च 1971 को ढाका पहुँच गये। याहिया खाँ अपने साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अब्दुल हमीद, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर जनरल पीरजादा, मेजर जनरल उमर तथा छः

बिग्रेडियरों को भी लाए थे। याहिया खाँ ने भुट्टो तथा अन्य पाकिस्तानी नेताओं को ढाका बुलाया। भुट्टो अपने बारह समर्थकों के साथ आये।

16 मार्च से वार्ता प्रारम्भ हुई।अन्ततोगत्वा 25 मार्च को बंगालियों की भ्राँति टूट गई जब शेख मुजीब, जुल्फिकार और याहिया खाँ की वार्ता एकाएक भंग हो गई और याहिया खाँ बंगालियों के दमन की पूर्ण व्यवस्था करके चुपचाप ढाका को छोड़कर करॉची रवाना हो गये तथा टिक्का खाँ को मुजीब को गिरफ्तार करने तथा विद्रोह का पूर्ण दमन करने का आदेश दे आये, उनका स्पष्ट आदेश था– "सीधा कर दो उन्हें"। फिर क्या था, सेना ने 25 मार्च की अर्ध रात्रि को पूर्ण शक्ति के साथ बाँग्लादेश की निहत्थी जनता के साथ संहार, लूट, विध्वंस और बलात्कार का नंगा–नाच प्रारम्भ कर दिया। लंदन से प्रकाशित एक समाचार पत्र में पाकिस्तानी पत्रकार एन्थोनी मेस्केरेनहस के हवाले से कहा गया कि पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा 3 लाख से 5 लाख निरीह बंगालियों की हत्या कर दी है।

12 अप्रैल 1971 को स्वाधीन बाँग्लादेश की छः सदस्यीय मंत्रिमण्डल वाली सरकार का गठन किया गया जिसमें शेख मुजीब को राष्ट्रपति, नजरूल इस्लाम को उप–राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति अहमद ताजुद्दीन को प्रधानमंत्री, मुस्ताक अहमद को विदेशमंत्री, और मंसूर अली व कमरूजमा को अन्य मंत्रियों का काम सौंपा गया। 17 अप्रैल 1971 को बाँग्लादेश के कार्यवाहक राष्ट्रपति सैयद नजरूल इस्लाम ने बाँग्लादेश सार्वभौमिक जनतांत्रिक गणराज्य के स्थापना की औपचारिक घोषणा की।

पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना व मुक्ति वाहिनी के बीच गुरिल्ला युद्ध चल रहा था जिससे पूर्वी पाकिस्तान में आतंक की स्थिति पैदा हो गयी थी। धीरे–धीरे भारत आने वाले इन शरणार्थियों की संख्या 1 करोड़ तक जा पहुँची। भारत आये इन शरणार्थियों पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 2 रूपये खर्च होते थे। इस प्रकार भारत को प्रतिदिन 2 करोड़ रूपये शरणार्थियों पर खर्च करने पड़ रहे थे। इससे भारत की अर्थ–व्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ रहा था।

पूर्वी पाकिस्तान में जबरदस्त प्रक्रिया हुई और इसी के साथ आवामी लीग द्वारा अहिंसक प्रतिरोध प्रारम्भ किया गया, जो आगे चलकर क्रान्ति के रूप में परिवर्तित हो गया। भारतीय उपमहाद्वीप में होने वाले इस मुक्ति–संघर्ष के परिणामस्वरूप लगभग एक करोड़ शरणार्थी भारत आये। शरणार्थी समस्या के चलते भारत–पाकिस्तान युद्ध जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और एक नये राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ।

सन्दर्भ ग्रंथ

1. के0पी0 मिश्रा : दि रोल ऑफ दि यू0एन0 इन दि इन्डो–पाकिस्तान कान्टीनेन्ट, विकास पब्लिकेशंस दिल्ली–1971 .
2. कुलदीप नैय्यर, डिस्टेन्ट नेबर्स : एटैल आफ दि सब कोन्टीनेन्ट, विकास पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1972,
3. कवलेश्वर राय "भारत की विदेश नीति" किताब महल, इलाहाबाद, 1987
4. एस0पी0 कश्यप, बाँग्लादेश : बैकग्राउण्ड एवं पर्सपेक्टिव, विकास पब्लिकेशन, दिल्ली, 1981,
5. मो0 समसुल हक, बांग्लादेश इन इंटरनेशनल पालिटिक्स : दि डिलिम्माज ऑफ दि वीक स्टेट्स, यूनीवर्सिटी प्रेस लि0, ढाका, 1993
6. जुल्फिकार अली भुट्टो, दि ग्रेट ट्रेजडी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पब्लिकेशन, रावलपिंडी, 1971
7. एस0सी0 वोरा, ज्यॉग्राफी आफ वेस्ट बंगाल, नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया, 1978

8. बाबूराम पाण्डेय, बांग्लादेश का मुक्ति संघर्ष : एक भूस्त्रातिजिक एवं राजनीतिक अध्ययन, प्रकाश बुक डिपो, बरेली, 1988 .
9. जे0ए0 नायक, भारत, रूस, चीन और बाग्लादेश, एस0 चाँद एण्ड कम्पनी, 1972.
10. जमीलुद्दीन अहमद, स्पीचेस एण्ड राइटिंग आफ मिस्टर जिन्ना, वा0–2, लाहौर, 1964
11. बैंडिक्ट कोस्टा, डिसमेम्बरमेंट ऑफ पाकिस्तान, लुधियाना, 1973, पृ0 51.
12. जी0डब्ल्यू0 चौधरी, बांग्लादेश व्हाई इट हैपेण्ड, इंटरनेशनल अफेयर्स, वा0–48, नं0–2, अप्रैल 1972
13. एन्थोनी मस्केरेनहस, द रेप ऑफ बाग्लादेश, विकास पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 1972.
14. बांग्लादेश डाक्यूमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया पब्लिकेशन, दिल्ली, 1971
15. राजेश जैन, भारत–पाकिस्तान : बदलते रिश्ते, भावना प्रकाशन, दिल्ली, 2005,.
16. एस0पी0 वर्मा एण्ड विरेन्द्र नारायण, पाकिस्तान पालिटिकल सिस्टम इन क्राइसेस इमरजेन्सी ऑफ बाँग्लादेश, साउथ एशिया स्टडीज सेन्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर, 1972,
17. मोहम्मद अयूब खाँ, पाकिस्तान्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इंटरनेशनल एफेयर्स, रायल
18. इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एफेयर्स, वा0–43, इश्यू–1, जनवरी 1967,
19. रविन्द्रनाथ त्रिवेदी, दि लीजेसी ऑफ दि प्लाइट ऑफ हिन्दूज इन बांग्लादेश पार्ट–7, एशियन ट्रिब्यून, ढाका, 2007.
20. अनुपम त्यागी, भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध, रिजेन्सी पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2004,
21. जी0डब्ल्यू0 चौधरी, दि लास्ट डेज ऑफ पाकिस्तान : ए पर्सनल एकाउंट,
22. इंटरनेशनल एफेयर्स, रायल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एफेयर्स, वा0–49, इश्यू–2, 1973,
23. सलमान तासीर, भुट्टो पॉलिटिकल बॉयोग्राफी, विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1980,
24. एस0आर0 चौधरी, दि जीनियस ऑफ बांग्लादेश, स्टडी इन इंटरनेशनल लीगल नार्म एण्ड परमीसिव कांसियेन्स, बम्बई, 1972.
25. अल्ताफ गौहर, पाकिस्तान : अयूब खान अब्डिक्शन, थर्ड वर्ल्ड क्वाटर्ली, वा0–7, इश्यू–1, जनवरी 1985
26. शिव बहादुर सिंह, पाकिस्तान शासन एवं राजनीति, गंगाराम एण्ड ग्रैंडसन्स, वाराणसी, 2002, व्हीलर, रिचर्ड्स, दि पालिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, कॉर्नेट यूनीवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क, 1970,
27. कपिल काक, इण्डियाज ग्राण्ड स्ट्रेटेजी फॉर दि 1971 वार, सी0एल0ए0डब्ल्यू0एस0 जर्नल, समर, 2012.
28. मेजर जनरल सुखवंत सिंह, "द लिबरेशन ऑफ बाँग्लादेश", अंक 1, लांसर पब्लिशर्स नई दिल्ली–1980
29. स्टेनले ए0 वूल्पर्ट, जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान : हिज लाइफ एण्ड टाइम्स, आक्सफोर्ड युनीवर्सिटीप्रेस, न्यूयार्क, 1993.
30. सुखवीर चौधरी, इण्डो–पाक, वार एण्ड बिग पावर, त्रिमूर्ति पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 1972.
31. डी0आर0 मानकेकर, भारत, पाकिस्तान निर्णायक युद्ध, राजपाल एण्ड सन्स पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 1972.